इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 17 | अंक संख्या 3 | अक्तूबर, 2024 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
विनियामक के कथन.....3
बीमा.....5
आर्थिक संवेष्टन.....5
नयी नियुक्तियाँ.....5
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....7
बाजार की खबरें.....8
नयी पहलकदमी.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

पर्यवेक्षित संस्थाएं स्वर्ण ऋण नीतियों की समीक्षा करें: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षित संस्थाओं को कहा है कि स्वर्ण ऋणों पर अपनी नीतियों, प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं में कमियों का पता लगाएँ तथा सुधार हेतु समुचित कदम उठाएँ। शीर्ष बैंक द्वारा पाई गई कमियों में निम्न शामिल हैं:

(i) ऋणों की सोर्सिंग व आकलन में अन्य पक्षों के इस्तेमाल में दोष;

(ii) ग्राहक की मौजूदगी के बगैर स्वर्ण का मूल्य निर्धारण;

(iii) अपर्याप्त समुचित सावधानी तथा स्वर्ण ऋणों के अंतिम उपयोग की निगरानी का अभाव;

(iv) चूककर्ता ग्राहक के स्वर्णाभूषणों व आभूषणों की नीलामी के दौरान पारदर्शिता न होना;

(v) ऋण से मूल्य (LTV) पर निगरानी का कमजोर होना;

(vi) जोखिम भार की गलत तरीके से गणना, आदि

पर्यवेक्षित संस्थाओं को इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक को 3 माह के भीतर देनी अपेक्षित है।

ऋण प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गम आवेदन यूपीआई के जरिए किया जाना है: सेबी

ऋण प्रतिभूतियों, अपरिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयर, नगरपालिक कर्ज़ प्रतिभूतियों व प्रतिभूत कर्ज़ लिखतों हेतु आवेदन प्रक्रिया को इक्विटी शेयरों तथा परिवर्तनीय लिखतों हेतु आवेदन प्रक्रिया के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने 5 लाख रुपए तक की आवेदन राशि हेतु निधियाँ केवल यूपीआई का प्रयोग कर ब्लॉक करने का अधिदेश दिया है। मध्यस्थों (नामत: सिंडिकेट सदस्यों, पंजीकृत शेयर दलालों, निर्गम के पंजीयक, ट्रांसफर एजेंट व डिपाजिटरी भागीदार) के जरिए ऐसी प्रतिभूतियों में सभी व्यैक्तिक निवेशकर्ताओं के लिए यह बदलाव 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। तथापि, सार्वजनिक निर्गमों में आवेदन करने हेतु निवेशकों को अन्य तरीकों यथा स्व-प्रमाणित सिंडीकेट बैंकों, अथवा स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफार्म के जरिए आवेदन करने का विकल्प अभी भी उपलब्ध होगा।

वाणिज्यिक पेपर भुगतान की स्थिति की सूचना देने हेतु संस्थाओं को कम रिपोर्टिंग समय मिलेगा

सेबी ने सूचीबद्ध वाणिज्यिक पेपर रखने वाली संस्थाओं को उनके भुगतान दायित्व की स्थिति रिपोर्ट करने का समय दो कार्यदिवसों के भीतर से घटा कर एक कार्यदिवस के भीतर कर दिया है। यह बदलाव अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों हेतु मौजूदा आवश्यकता के अनुरूप है तथा सूचीबद्धता दायित्वों व प्रकटन अपेक्षाओं (LODR) के नियमों का ध्यान रखते हुए किया गया है जिनमें अपेक्षित है कि ऐसी संस्थाएं ब्याज, लाभांश अथवा मूलधन की चुकौती को शामिल कर अपने भुगतान दायित्वों की स्थिति रिपोर्ट किया करें।

वैकल्पिक निवेश निधियों के मूल्यांकन ढांचे में उद्योग समूह की प्रतिक्रिया के अनुरूप सेबी द्वारा संशोधन

उद्योग समूह की प्रतिक्रिया के मद्देनज़र, सेबी ने वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यांकन हेतु अपने ढांचे को संशोधित कर दिया है। पात्र वैकल्पिक निवेश निधि संघ द्वारा सहमत मूल्यांकन दिशानिर्देशों को शामिल कर इसने, आस्तियों के मूल्यांकन संबंधी जटिलता को भी दूर कर दिया है। साथ ही, निवेशिती कंपनियों के मूल्यांकन की, निष्पादन बेंचमार्किंग एजेंसियों को रिपोर्टिंग हेतु अब सात माह (जो पहले छ: माह था) का समय मिलेगा ।

ऋण जोखिम के प्रबंधन हेतु म्यूचुअल फंड अब क्रेडिट डिफ़ाल्ट स्वैप खरीद-बेच सकते हैं: सेबी

कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार में तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को ऋण जोखिम के प्रबंधन हेतु क्रेडिट डिफ़ाल्ट स्वैप खरीदने–बेचने की अनुमति दे दी है। इसके पहले, म्यूचुअल फंड क्रेडिट डिफ़ाल्ट स्वैप का उपयोग, उनके द्वारा धारित कॉर्पोरेट बॉण्ड के ऋण जोखिम के समक्ष सुरक्षा के क्रय मात्र हेतु कर सकते थे। ये संव्यवहार एक वर्ष से अधिक की अवधि वाली स्थिर परिपक्वता योजनाओं तक सीमित थे। परिवर्तित मानदंड कतिपय शर्तों के अधीन हैं।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

एमएसएमई (MSME) विनिर्माता निर्यातकों को ब्याज सहायता योजना की अवधि के विस्तार से लाभ

वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत के जावक लदानों को सहायता देने के उद्देश्य से, एमएसएमई विनिर्माता निर्यातकों हेतु लदान पूर्व एवं पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण योजना को सरकार ने महीने भर के लिए बढ़ा दिया। इससे प्रतियोगी दरों पर रुपया निर्यात ऋण लेने हेतु निर्यातकों को 30 सितंबर 2024 तक का समय मिल गया। वार्षिक निवल सहायता राशि की उच्चतम सीमा संबन्धित वित्त वर्ष हेतु प्रति आयात निर्यात कोड (आईईसी) हेतु वार्षिक 10 करोड़ रुपए निर्धारित है। तदनुसार, 1 अप्रैल 2024 से शुरू वित्त वर्ष के लिए एमएसएमई विनिर्माता निर्यातकों हेतु प्रति आयात निर्यात कोड 5 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा लगाई गई थी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

बैंक ऋणों का क्षेत्रवार अभिनियोजन

बैंक ऋणों के क्षेत्रवार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों को ऋण की स्थिति अगस्त 2023 के दौरान 16.5% की तुलना में अगस्त 2024 में 17.7% (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि के साथ मजबूत बनी रही।
- अगस्त 2023 में 5.3% की तुलना में अगस्त 2024 में 9.8% (वर्षानुवर्ष) के साथ उद्योग जगत को ऋण वृद्धि में मजबूती आई। प्रमुख उद्योगों में, 'रसायनों तथा रासायनिक उत्पादों', 'खाद्य प्रसंस्करण', 'पेट्रोलियम,कोयला उत्पादों व नाभिकीय इंधनों' तथा 'अवसंरचना' को ऋण में अगस्त 2024 में, एक वर्ष पूर्व उनकी संबंधित वृद्धि दरों की तुलना में उच्चतर वृद्धि दर्ज़ की गई।
- एक वर्ष पहले के 21.0% की अपेक्षा सेवा क्षेत्र को ऋणों में वृद्धि घट कर अगस्त 2024 में 15.6% (वर्षानुवर्ष) रही।
- एक वर्ष पूर्व के 18.3% की तुलना में अगस्त 2024 में व्यैक्तिक ऋणों में वृद्धि घट कर 16.9% रही, यह मुख्यत: 'अन्य व्यैक्तिक ऋणों' तथा 'वाहन ऋणों' में वृद्धि में दर्ज कमी के कारण है।

विनियामक के कथन

एनबीएफआई (Non-Banking Financial Institution) निजी ऋण से जुड़े जोखिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास का वक्तव्य

ब्रेटन वुड्स कमिटी, सिंगापुर द्वारा आयोजित फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फोरम 2024 में, वैश्विक वित्तीय स्थायित्व: जोखिम तथा अवसर विषय पर बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने वित्तीय मध्यस्थता में बैंकों से इतर संस्थाओं के फैलाव पर चिंता व्यक्त की क्योंकि इनसे वित्तीय स्थायित्व को जोखिम उत्पन्न हो सकता है। घरेलू व वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआई) के आकार, जटिलता एवं अन्त: संबद्धता से जोखिम कैसे आ सकता है, इस पर प्रकाश डालते हुए श्री दास ने उल्लेख किया कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को उनकी एनबीएफआई में कमजोरियों के चलते बाज़ार संचालन में समय-समय पर व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है। श्री दास ने आगे एक अन्य जोखिम नामत: निजी ऋण की चर्चा की। विगत दशक में चार गुना बढ़ कर निजी ऋण न्यून या नकारात्मक आय, उच्च लीवरेज वाली मिडल मार्केट फर्मों हेतु कॉर्पोरेट वित्तपोषण का प्रमुख माध्यम बन गया है पर इसमें उच्च गुणवत्ता की संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं होती। गवर्नर महोदय ने वैश्विक वाणिज्यिक रियल स्टेट (सीआरई) क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता भी बताई। बैंक अपनी ऋण बहियों में अपेक्षाकृत उच्च सीआरई कवरेज अनुपात के कारण प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित सीआरई हानियों के प्रति अधिक संवेदनशीलता दर्शा रहे हैं। बैंकों के तुलन पत्रों व प्रणालीगत स्थिरता के प्रति जोखिमों को कुशलता से रोकने हेतु श्री दास ने सजग रहने तथा समय रहते विनियामक उपाय अपनाने पर ज़ोर दिया।

आर्थिक प्रगति हेतु बहुआयामी, बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने का भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा आह्वान

फिक्की (FICCI) तथा आईबीए (IBA) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वार्षिक एफआईबीएसी (FIBAC) 2024 में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि उभरती से 2047 तक उन्नत अर्थव्यवस्था में तब्दील होने हेतु हमारी अर्थव्यवस्था को बहुआयामी तथा बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। उनका कहना था कि हमें आपूर्ति एवं मांग दोनों पक्षों से

वृद्धि के सारे तरीके लागू करने चाहिए। वित्तीय समावेशन का विस्तार कर, ऋणों व अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुँच को व्यापक बना कर तथा समग्र समावेशी वृद्धि का साथ देते हुए वित्तीय क्षेत्र को भी इसमें अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। इसे डिजिटल बैंकिंग में नवोन्मेष को बढ़ावा देना चाहिए, संधारणीय वित्त को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा ऐसा मज़बूत वित्तीय तंत्र निर्मित करना चाहिए जो उभरती चुनौतियों का सामना कर सके तथा ऊंची वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना तथा एमएसएमई (MSME) को सहायता प्रदान करना भी महत्वपूर्ण विचारणीय विषय हैं।

केंद्रीय बैंक व्यापक तरीकों से व्यापक आर्थिक स्थिरता स्थापित कर रहे हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास

प्रथम हिमालय शमशेर स्मृति व्याख्यान में अपना संबोधन देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि समग्र व्यापक आर्थिक स्थिरता जिसमें मूल्य स्थिरता, सतत् वृद्धि एवं वित्तीय स्थायित्व शामिल हैं, के विस्तृत अधिदेश को लागू करने हेतु केंद्रीय बैंकों ने अपने उपायों में प्रभावी विस्तार किया है। पारंपरिक नीतिगत साधनों के साथ वे नकारात्मक ब्याज दरों, मियादी ऋण सुविधाओं, आस्ति क्रय कार्यक्रमों तथा अग्र मार्गदर्शन जैसे अपारंपरिक नीतिगत साधनों का भी उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक व्यवधानों तथा भू-आर्थिक विभाजन केंद्रीय बैंकों द्वारा इन दिनों सामना की जा रही महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।

भारत की विकास गाथा को आकार सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से मिलेगा: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ माइकल डी पात्रा

कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) द्वारा आयोजित 'फाइनेंसिंग 3.0 समिट' को संबोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ माइकल डी पात्रा ने कहा कि आगे चल कर, बढ़ती आय के चलते, भारतीय परिवारों द्वारा उनकी वित्तीय आस्तियों के निर्माण पर ज़ोर दिए जाने की संभावना है। डॉ पात्रा ने भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में क्रांतिकारी योगदान करने वाले पाँच सामरिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। इनमें से पहला अवसंरचना को वित्तपोषण हेतु है जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी अपेक्षित है। दूसरा अभी भी अल्पसेवित एमएसएमई क्षेत्र है। तीसरा, तकनीकी बदलावों के अनुरूप मानव संसाधन को कौशलयुक्त करने हेतु वित्त की आवश्यकता है जिसमें निजी क्षेत्र का सहयोग, बांड निर्गम, स्किल वाउचर, वेंचर पूंजी, ई लर्निंग केंद्र, स्टार्ट अप आदि वांछित हैं। चौथा संधारणीय पहलों यथा हरित हाइड्रोजन मिशन व नेट जीरो लक्ष्यों के निधियन हेतु जलवायु वित्तपोषण है। पांचवा, भारत की डिजिकरण की यात्रा हेतु निधि की व्यवस्था करना है।

एमएसएमई क्षेत्र में अधिक महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे.

हुबली में अग्रणी जिला प्रबंधकों तथा जिला विकास प्रबंधकों के सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. ने कहा कि देश के दूरस्थ इलाकों तक बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं की पहुँच में सहायता के लिए एमएसएमई क्षेत्र में लैंगिक अंतर को पाटना जरूरी है। भारत में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई 20% से भी कम हैं क्योंकि उन्हें निधियन तक सीमित पहुँच व सामाजिक बंधनों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों हेतु निर्मित बैंकिंग योजनाओं के जरिए इन मुद्दों का समाधान करना एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा सकता है।

अवसंरचना क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी अपेक्षित: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID) द्वारा आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर संगोष्ठी में अपने बीज वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने कहा कि अवसंरचना परियोजनाओं के दीर्घ जीवन काल के चलते परियोजना के विभिन्न चरणों में विशेषज्ञता वाली वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी अपेक्षित होती है जिससे प्रक्रिया में पुनर्वित्तीयन, इन संस्थाओं के बीच परियोजनाओं के अंतरण तथा अधिग्रहण द्वारा मदद मिलती है।

समय पर वित्त, प्रौद्योगिकी चालित प्रणालियाँ संधारणीय कृषि को बढ़ावा दे सकती हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे.

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे की मेजबानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन में अपने बीज वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. ने कहा कि उग्र मौसम स्थितियों यथा गंभीर सूखे व बाढ़ हेतु संधारणीय कृषि महत्वपूर्ण समाधान

है। इसे पारंपरिक कृषि प्रथाओं को प्रौद्योगिकी चालित प्रणालियों में बदल कर, कृषि जिंसों के प्रसंस्करण व संरक्षण जो फार्म स्तर पर मूल्य वर्द्धन में योगदान करेगा, को बढ़ाकर, फसल उत्पादन प्रणालियों को जलवायु अनुकूल कृषि के साथ जोड़ कर तथा इन सभी की पूर्ति के लिए पर्याप्त तथा समय पर वित्तपोषण सुनिश्चित कर हासिल किया जा सकता है। कृषक उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisations) जैसे समूहों की भूमिका; मूल्य शृंखला तथा गोदाम को वित्तपोषण; वित्तीय प्रौद्योगिकी को अपनाना; तथा सरकारी योजनाओं के साथ मिल कर पूंजी निर्माण, कृषि की संधारणीयता हासिल करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे।

लघु वित्त बैंक द्वारा अभिशासन को सुदृढ़ करना, दायित्वपूर्ण कर्ज प्रथा अपनाना अनिवार्य: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे.

लघु वित्त बैंकों के निदेशकों के सम्मेलन में बोलते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. ने कहा कि व्यवसाय में संधारणीय वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु भारत के लघु वित्त बैंकों को अभिशासन अनिवार्यत: सुदृढ़ करना चाहिए तथा दायित्वपूर्ण कर्ज प्रथा अपनानी चाहिए। लघु वित्त बैंकों के बोर्ड, शीर्ष प्रबंधन स्तर पर समुचित उत्तराधिकार आयोजना अवश्य सुनिश्चित करें ताकि नेतृत्व में व्यवधान के बगैर मजबूत प्रबंधन ढांचा बना रहे। छिपे व उभरते जोखिमों की समय पर पहचान करने हेतु उनका सतर्क रहना जरूरी है।

बीमा

पॉलिसीधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु आईआरडीएआई (IRDAI) द्वारा मानदंडों का सुगमीकरण

जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमाकर्ता अब महत्वपूर्ण जानकारी जो बीमा संविदा के विभिन्न चरणों पर लागू हो, का सारांश उपलब्ध कराएंगे। सभी बीमा खंडों हेतु बीमाकर्ताओं द्वारा ग्राहक सूचना पत्रक (सीआईएस) प्रदान किया जाना होगा। इस सीआईएस में पॉलिसी की मुख्य बातों, लाभों तथा विवर्जनों का उल्लेख होगा। यदि ग्राहक अनुरोध करे तो प्रस्ताव फार्म तथा सीआईएस क्षेत्रीय भाषा में भी अवश्य उपलब्ध कराए जाएं। जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा पॉलिसियों की शर्तों व निबंधनों की समीक्षा हेतु पॉलिसीधारकों को 30 दिनों का फ्री लुक समय भी मिलेगा।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा, अगस्त 2024 की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- स्थिर कीमतों पर वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 6.7% की वृद्धि हुई।
- स्थिर कीमतों पर वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में औद्योगिक क्षेत्र 8.3% बढ़ा।
- सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि जारी रही, इसमें वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 7.2% की वास्तविक वृद्धि देखी गई।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में अप्रैल-जुलाई 2024 में वर्षानुवर्ष 5.2% की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 25 के शुरू के पाँच महीनों में भारत से माल निर्यात में वर्षानुवर्ष 1.1% की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 25 के शुरू के पाँच महीनों में भारत का सेवाओं का निर्यात 10.8% बढ़ गया।
- सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह में उछाल के चलते भारत को निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह वित्त वर्ष 25 के शुरू के चार महीनों में 52.4% बढ़ा।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण संवितरण में वित्त वर्ष 25 के शुरू के चार महीनों में सतत् स्थिर वृद्धि जारी रही जो स्वस्थ बाजार गतिकी का परिचायक है-वृद्धि के अवसरों का स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री के वी एस मनियन	एमडी तथा सीईओ, फेडरल बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	27 सितंबर 2024 के दिन करोड रुपए	27 सितंबर 2024 के दिन मिलियन अमरीकी डालर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डालर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5900138	704885	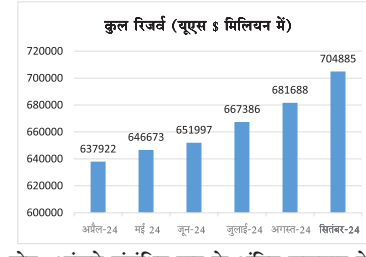
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5157443	616154	
1.2 सोना	550741	65796	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	155249	18547	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	36706	4387	

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 30 सितंबर 2024 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें – अक्तूबर 2024 माह हेतु लागू

मुद्रा	दर
अमरीकी डॉलर	4.83
जीबीपी	4.95
यूरो	3.415
जापानी येन	0.226
कनाडाई डॉलर	4.3000
आस्ट्रेलियाई डॉलर	4.35
स्विस फ्रैंक	1.208417

मुद्रा	दर
न्यूज़ीलैंड डॉलर	5.25
स्वीडिस क्रोन	3.401
सिंगापुर डॉलर	3.1705
हांगकांग डॉलर	4.45006
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	3.1230

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

ऋण चूक स्वैप (Credit Default Swap)

ऋण चूक स्वैप से आशय उस ऋण डेरिवेटिव संविदा से है जिसमें एक प्रतिपक्षकार (प्रोटेक्शन विक्रेता) एक संदर्भ संस्था से संबन्धित ऋण इवेंट के मामले में अन्य प्रतिपक्षकार (प्रोटेक्शन क्रेता) को भुगतान करने को प्रतिबद्ध होता है और बदले में प्रोटेक्शन क्रेता, प्रोटेक्शन विक्रेता को संविदा के परिपक्व होने अथवा ऋण इवेंट होने, इनमें से जो पहले हो, तक आवधिक (प्रीमियम) भुगतान करता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

पूरक (Bridge Loan) **ऋण**

पूरक ऋण उस समय तक उपयोग किया जाने वाला अल्पावधि ऋण होता है जब तक एक व्यक्ति या कंपनी स्थायी वित्तपोषण न प्राप्त कर ले या मौजूद ऋण न चुका दे। ऋणी इससे तुरंत नकदी देकर वर्तमान दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। पूरक ऋणों पर ब्याज दरें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं और ये आमतौर पर किसी प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूति यथा रियल स्टेट या व्यवसाय के माल की जमानत पर दिए जाते हैं।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अक्तूबर 2024 माह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
कारोबार नैतिकता व कॉर्पोरेट अभिशासन पर कार्यक्रम	15-16 अक्तूबर 2024	वर्चुअल
प्रमाणित ट्रेजरी पेशेवरों हेतु परीक्षा उपरांत प्रशिक्षण	15-17 अक्तूबर 2024	वर्चुअल
ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पर कार्यक्रम	16-17 अक्तूबर 2024	लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई
निवारक सतर्कता एवं धोखाधड़ी प्रबंधन पर कार्यक्रम	16-18 अक्तूबर 2024	वर्चुअल
अनुशासन प्रबंधन, अन्वेषण तथा अनुशासनिक कार्य/कारवाई पर कार्यक्रम	17-19 अक्तूबर 2024	वर्चुअल
प्रभावी नेतृत्व विकास एवं सॉफ्ट स्किल्स पर कार्यक्रम	21-25 अक्तूबर 2024	आईआईबीएफ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, नार्दर्न जोन, नयी दिल्ली-110016
बैंकों में ऋण व परिचालन जोखिम के न्यूनीकरण की रणनीतियों पर कार्यक्रम	23-24 अक्तूबर 2024	वर्चुअल
लेखा एवं लेखापरीक्षा पेशेवरों हेतु कार्यक्रम	28-30 अक्तूबर 2024	वर्चुअल

संस्थान समाचार

वार्षिक आम बैठक

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ) ने अपनी 97वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन 21 सितंबर 2024 को प्रात: 11:30 बजे वीसी/ओएवीएम फार्मेट में किया।

आईआईबीएफ और इग्नू- जेएआईआईबी/सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए क्रेडिट अंतरण योजना हेतु समझौता

2023 के संशोधित पाठ्यक्रम के तहत जेएआईआईबी/सीएआईआईबी योग्यता हासिल करने वाले आईआईबीएफ के सदस्यों को एमबीए (बैंकिंग व वित्त) में प्रवेश देने के लिए आईआईबीएफ और इग्नू ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एमबीए (बैंकिंग व वित्त) की अधिकतम अवधि के भीतर, आईआईबीएफ से जेएआईआईबी/सीएआईआईबी के संगत विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इग्नू, एमबीए (बैंकिंग व वित्त) के 28 कोर्सों में अधिकतम 5 कोर्सों तक की छूट/20 क्रेडिट का ट्रांसफर देगा। अधिक विवरण निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

http://www.ignou.ac.in/ignou/aboutignou/school/soms/credittransfer

प्रमाणित वित्तीय आयोजक प्रमाणन कार्यक्रम हेतु आईआईबीएफ का एफपीएसबी के साथ समझौता

संस्थान ने वित्तीय आयोजना पेशे हेतु वैश्विक मानक निर्धारक निकाय की भारतीय अनुषंगी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय आयोजक (सीएफपी) प्रमाणन कार्यक्रम की स्वामी एफपीएसबी इंडिया के साथ कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण भागीदारी के तहत, आईआईबीएफ से सीएआईआईबी योग्यता पूरी कर चुके तथा बीएसएफआई क्षेत्र में तीन वर्षों का मान्य

अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीएफपी प्रमाणन के प्रथम तीन मॉड्यूल उत्तीर्ण करने से छूट होगी तथा वे फास्टट्रैक राह से एफपीएसबी इंडिया के समन्वित वित्तीय आयोजना मॉड्यूल में सीधे नामांकन करा सकेंगे। अधिक जानकारी iibf.org.in पर मिलेगी।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

अक्तूबर–दिसंबर 2024 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय "बचत तथा निवेशों हेतु उभरते अवसर" रखा गया है।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण सूचनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान की प्रथा रही है कि विनियामक (कों) द्वारा जारी हाल के परिवर्तनों/दिशानिर्देशों संबंधी प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से वास्तविक परीक्षा तिथियों तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है।

इन मुद्दों के कारगर समाधान हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि संस्थान द्वारा सितंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 30 जून 2024 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी।

बाजार की खबरें

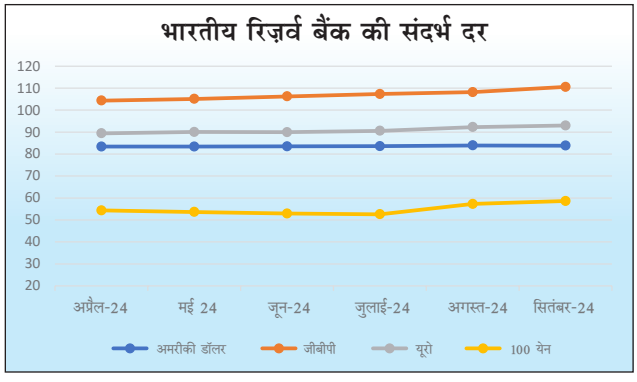

स्रोत: एफबीआईएल

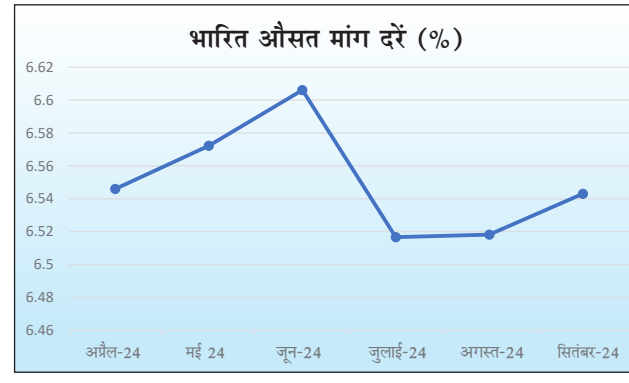

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

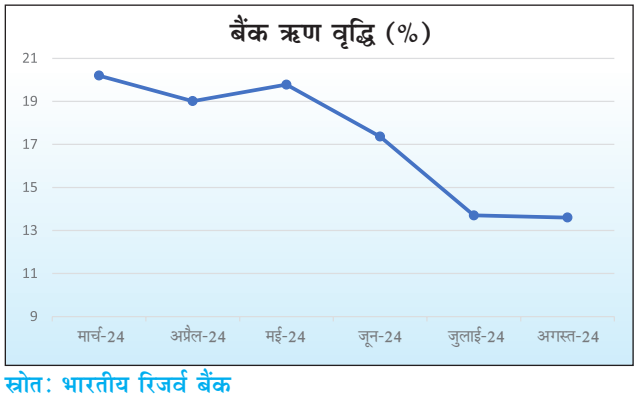

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

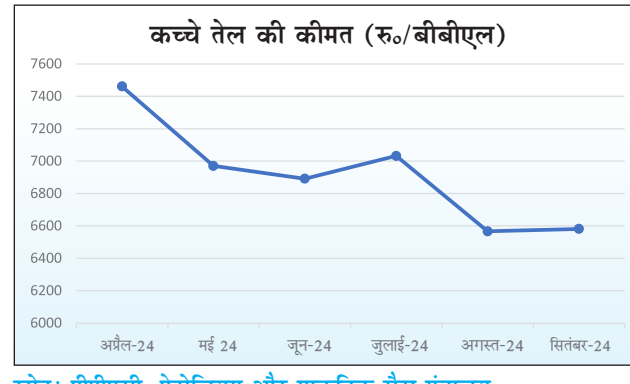

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

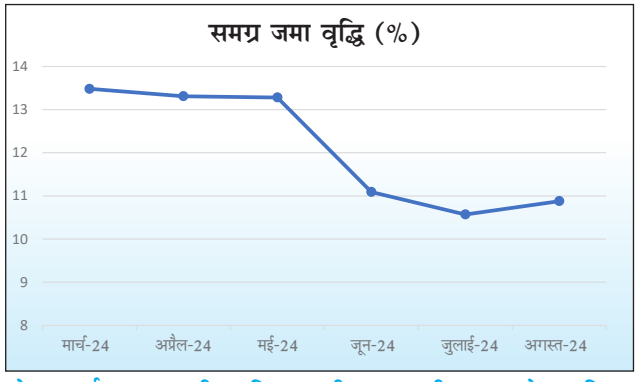

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, सितंबर, 2024

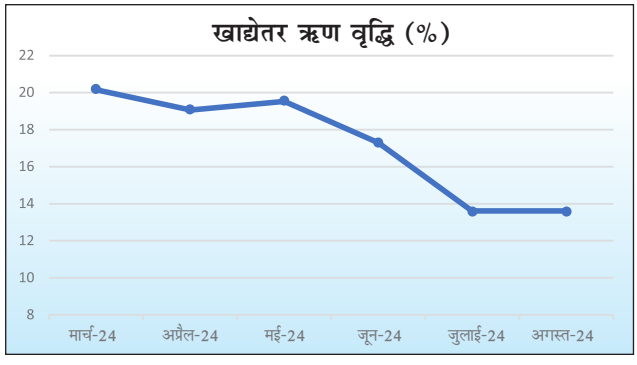

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, सितंबर 2024

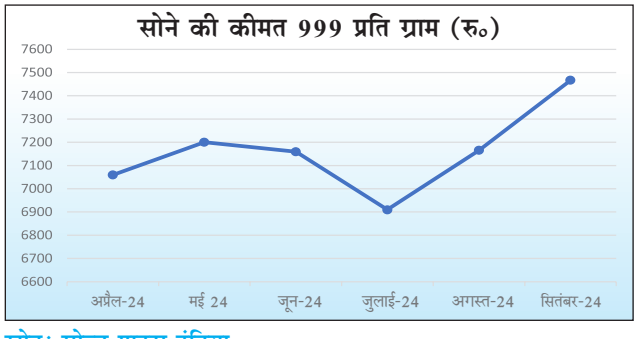

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

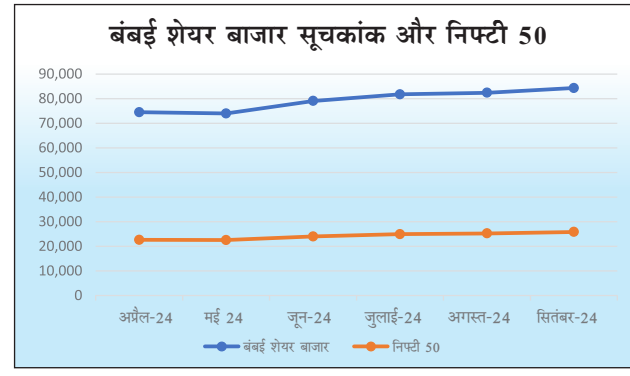

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in